

Women yoga practitioners outnumber men

Ahmedabad, June 2017: There seems to be a rise of about 20 per cent in the number of Yoga practitioners in urban centers of India with women outnumbering men by significant margin, noted a just-concluded random survey conducted by ASSOCHAM Social Development Foundation. ASSOCHAM Social Development Foundation interacted with about 500 people including both working and non-working people with an equal number of men and women in the age group of 20-45 years during the course of past fortnight. The survey was conducted in 10 cities of – Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi-NCR, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Lucknow and Mumbai to ascertain if there has been any rise in number of yoga practitioners and what are the reasons for doing Yoga.

"Popularity of Yoga in India has been growing by leaps and bounds thereby giving a rise to number of people who are practicing it owing to its positive impact on mind and body of the practitioners," said Mr D.S. Rawat, secretary general of ASSOCHAM while releasing the findings of the chamber's survey. "However, there is a dearth of Yoga trainers as such the government both at the centre and state level should introduce a dedicated three year bachelor degree course in yoga to enable more and more youth in the country to become competent and professional yoga trainers even after passing the XII standard thereby spurring entrepreneurship and job generation," said Mr Rawat.

Interestingly, over half of the total respondents (275) said they practice Yoga and have experienced its significant positive results like relieving stress, developing positive self image, good physique, flexibility, sound and agile bodies, positive mindset and others. While about 20 per cent of these said they have recently (in past year or so) started practising Yoga and are likely to continue doing it considering the immense benefits of this ancient form of exercise on their physical and mental fitness.

घरेलू योग इंडस्ट्री 2 साल में ₹1.5 लाख करोड़ की होगी

हेल्थ को लेकर अवेयरनेस के चलते वर्ल्ड योग इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ रुपये के ऊपर पहुंची, 20% सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है योग का कारोबार

[जोसफ बर्नाड | नई दिल्ली]

देश में नहीं बल्कि में विदेश में भी योग को लेकर लोगों का क्रेज बढ़ रहा है। यही कारण है कि योग की इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है। भारत में योग अभी एक ऑर्गनाइज्ड इंडस्ट्री की शक्ल नहीं ले पाया है, मगर भारत की वेलनेस इंडस्ट्री 49,000 करोड़ रुपये पर पहुंच चुकी है, जिसमें 40 फीसदी हिस्सा सर्विसिज का है। केंद्र की मेक इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड योग इंडस्ट्री करीब 5.32 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इधर इंडस्ट्री चैंबर फिक्की का कहना है कि अमेरिका और यूरोप में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। यही कारण है कि योगा इंडस्ट्री की ग्रोथ कुल 20 फीसदी सालाना के पास पहुंच गई है। जहां तक भारत की बात है तो यहां योगा इंडस्ट्री साल 2019-20 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, योग से जुड़े प्रॉडक्ट्स की डिमांड तेजी के साथ बढ़ रही है। उन

कंपनियों की बल्ले-बल्ले हो रही है, जो योगा कुशन, योगा मैट, योगा ब्लैकेट वगैरह बनाती हैं। इन कंपनियों के कारोबार में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। पिछले दो सालों से इन प्रॉडक्ट्स की लगातार डिमांड बढ़ रही है। फिक्की का मानना है कि भारत में आईटी के बाद वेलनेस इंडस्ट्री दूसरे नंबर पर है। आने वाले 4 से 5 साल में यह नंबर 1 पर भी

आ सकती है। इसमें योग और योग से जुड़ी एसेसरीज की हिस्सेदारी 50 फीसदी तक रहने का अनुमान है। ऐसा इसलिए संभव है कि अमेरिकी सरकार की नीतियों से इंटरनेशनल स्तर पर आईटी सेक्टर में स्लोडाउन आने की संभावना है। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार योग की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते प्रशिक्षित योग ट्रेनरों की डिमांड बढ़ रही है।

P-नोट से निवेश पर होगी सख्ती

नई दिल्ली: शेयर मार्केट में ब्लैक मनी का फ्लो रोकने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी नोट्स) से जुड़े नियमों को और सख्त करने जा रहा है। सेबी ने विदेशी ब्रोकर्स द्वारा इश्यू किए जाने वाले हर पी-नोट्स पर लेवी लगाने का फैसला किया है। हालांकि इस पर पूरी तरह से बैन नहीं होगा। हर इश्यू पर ब्रोकर्स को 65,000 रुपये रेगुलेटरी फी देनी होगी। सेबी का मानना है कि इस कदम से इस रास्ते के जरिए भारत में निवेश घट जाएगा। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कहना है कि हम पी-नोट्स निवेश पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा रहे हैं, इसके नियम सख्त किए गए हैं। दूसरी ओर, एनपीए की लड़ाई में आरबीआई को मार्केट रेगुलेटर सेबी का भी साथ मिल गया है। सेबी ने बड़ा फैसला लेते हुए एनपीए वाली कंपनियों को बेचने के नियम आसान कर दिए हैं।